कोलियरियों से प्राप्त कोयले को उदारीकृत बिक्री योजना के तहत पेशकश की जाती है । उपभोक्ताओं को अपने आर्डरों की बुकिंग कराने का अवसर क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक अहमदाबाद के माध्यम से भी प्रदान किए गए हैं ।

Energy efficient label products

1058. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in many countries it is mandatory for the manufacturers of home appliances to affix energy efficient label on their products;

(b) whether it is also a fact that this practice has not yet been adopted by the local manufacturers of such products;

(c) whether Government propose to direct the manufacturers of such appliances to have such a label on their products; and

(d) if so, by when and if not reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES) (SMT. KRISHNA SAHI): (a) As per the information available, energy labelling is being done on some domestic appliances in some countries.

(b) The concept of energy labelling on home appliances is not widely prevalent in India.

(c) No such proposal is presently under consideration.

(d) The process of identification of criteria for energy efficiency through standards has been initiated.

विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सर्वेक्षण

1059. **श्री भागमणि** :

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिविल निर्माण, कृषि, ईंटों के भट्ठों तथा स्टोन वर्क्स सेक्टर और होटलों में कार्यरत व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार एंव उनके कल्याण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्री (श्री जी.वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, जो श्रम मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, ने भवन और निर्माण उद्योग, ईंट भट्ठा उद्योग तथा पत्थर खदान उद्योग में लगे कर्मकारों की कामकाजी और रहन-सहन की परिस्थितियों के कुछ सर्वेक्षण करवाए हैं । ब्यूरो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सामान्य रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों के साथ पंचवर्षीय आधार पर आयोजित ग्रामीण श्रम जांचों के संबंध में रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है । कुछ सर्वेक्षणों के मुख्य-मुख्य निष्कर्ष सलंग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

भवन निर्माण, उद्योग ईंट भट्ठा उद्योग तथा पत्थर खदान उद्योग में लगे कर्मकारो की परिस्थितियों के संबधं में कराए गए सर्वेक्षणों के निष्कर्ष

I. दिल्ली में भवन और निर्माण उद्योग का सर्वेक्षण (1997-98)

सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिला कर्मकार कुल श्रम बल का लगभग 20% थी और अकुशल कार्यों में लगी थी । बालकों का नियोजन भी विद्यमान पाया गया था । दैनिक मजदूरी की अदायगी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार की जाती थी । कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत अदायगी को छोड़कर कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया नहीं करवाए जा रहे थे । कुशल कर्मकारों का लगभग 38% और अकुशल कर्मकारों का लगभग 56.7% ऋण ग्रस्त पाए गए ।

II. हरियाणा में ईंट-भट्ठा उद्योग का सर्वेक्षण (1982)

सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्पादन प्रयोजनों के लिए केवल पुरूष नियोजित थे । इनमें से 97% कर्मकार